

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
राकेश कुमार उर्फ चंदन मंडल एवं अन्य
बनाम

बिहार राज्य

2023 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) संख्या- 34

17 अगस्त 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे)

विचार के लिए मुद्दा

क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपीलार्थियों का दोषसिद्धि अभियोजन साक्ष्यों के आलोक में न्यायसंगत है?

हेडनोट्स

सूचक स्वयं प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। मुख्य गवाह सूचक की माता हैं जिनकी घटना स्थल पर उपस्थिति संदिग्ध नहीं है, किन्तु उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार, अभियोजन गवाहों की घटना स्थल पर उपस्थिति अत्यधिक संदेहास्पद है – चिकित्सक ने यह भी सुझाव दिया कि चोटें किसी कठोर सतह पर गिरने से भी हो सकती हैं। (पैरा 28, 31)

घटना की रीति, स्थल और सीमांकन के संबंध में तथ्यात्मक गवाहों के बयान में अनेक विरोधाभास, कमियाँ और असंगतियाँ हैं। अभियोजन अपनी बात संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा। अपील स्वीकार की गई। (पैरा 32, 33, 34)

न्याय दृष्टान्त

हबीब मोहम्मद बनाम हैदराबाद राज्य, ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 51; तकदीर समसुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य, ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 37; ब्रह्म स्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 280; रंजीत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 255; मनो दत्त बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2012) 4 एस.सी.सी. 79; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशन चंद, (2004) 7 एस.सी.सी. 629; सुनील कुमार शंभुदयाल गुप्ता बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2010) 13 एस.सी.सी. 657; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण गोपाल, ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 2154

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

मुख्य शब्दों की सूची

धारा 307 भा.दं.सं.; समान आशय; प्रत्यक्षदर्शी की विश्वसनीयता; चिकित्सीय प्रतिवेदन; संदेह का लाभ; घटना स्थल; गवाहों के विरोधाभास; आपराधिक न्यायशास्त्र; अभियोजन की विफलता; प्रतिपरीक्षण

प्रकरण से उत्पन्न

पिरीबाजार थाना कांड संख्या 10/2015

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्तओं की ओर से : श्री रबी भूषण, सुश्री राखी कुमारी, अधिवक्ता

उत्तरदातओं की ओर से : श्री मुकेश्वर दयाल, ए.पी.पी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं.34

थाना कांड संख्या-10 वर्ष-2015 थाना-पीरी बाजार, जिला-लखीसराय से उत्पन्न

=====

1. राकेश कुमार उर्फ चंदन मंडल, पिता- स्वर्गीय अघोरी मंडल, निवास/गांव -अभयपुर
कासवा, थाना- पीरी बाजार, जिला-लखीसराय
2. फंदूश मंडल उर्फ निर्भय मंडल पिता- स्वर्गीय अघोरी मंडल, निवास/गांव -अभयपुर
कासवा, थाना- पीरी बाजार, जिला-लखीसराय

... .. अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य सरकार

... ..उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं के लिए	:	श्री रवि भूषण, अधिवक्ता
		सुश्री राखी कुमारी, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए अधिवक्ता	:	श्री मुकेश्वर दयाल, सहायक लोक अभियोजक

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे

सी.ए.वी निर्णय

दिनांक : 17-08-2023

1. वर्तमान अपील, पीरी बाजार थाना कांड संख्या 10 से उत्पन्न जी.आर.

मामला संख्या 305/2015 के अनुरूप सत्र विचारण संख्या 165/2015 में विद्वान सत्र

न्यायाधीश, लखीसराय द्वारा पारित दिनांक 02.12.2022 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 03.12.2022 के दंडादेश के विरुद्ध है। जिसके तहत और अंतर्गत अपीलकर्ताओं को भा.दं.वि. (भारतीय दंड संहिता) की धारा 307 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उन्हें उक्त अपराध के लिए प्रत्येक को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये (10,000/- रुपये) के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर, उन्हें एक-एक वर्ष का कठोर कारावास भी भुगतना होगा।

2. सूचक (अ.सा.-4) की लिखित रिपोर्ट के अनुसार, घटना 24.02.2015 की लगभग सुबह 8:30 बजे की है, जिसके बाद पीरीबाजार के थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने प्राथमिकी दर्ज की।

3. अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि सूचक ने संक्षेप में बताया है, यह है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन यानी 24.02.2015 को सुबह लगभग 8.30 बजे, अपीलकर्ता और अन्य लोग सूचक के दरवाजे पर पहुँचे और उन्होंने गालियाँ देते हुए धमकी दी कि अगर मामला नहीं सुलझाया गया तो अपीलकर्ता और अन्य लोग उन्हें जान से मार देंगे। आगे बताया गया है कि जब सूचक की माँ ने गाली-गलौज का विरोध किया, तो अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों ने अपने हाथों में लाठी, डंडा और खंती लेकर सूचक की माँ के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह गिर पड़ी। शोर सुनकर सूचक दौड़कर आया और अपनी माँ को बचाया। सूचक ने दावा किया है कि बार-बार धमकी दी गई कि अगर मामला नहीं सुलझाया गया तो सभी को मार दिया जाएगा।

4. सूचक की लिखित रिपोर्ट के आधार पर, पीरीबाजार थाना कांड संख्या 10/2015 दिनांकित 24.02.2015 को (भा.दं.वि.) भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 325, 307/34 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। नियमित जांच की गई। गवाहों के बयान दर्ज किए गए और जांच पूरी होने पर, अपीलकर्ताओं के खिलाफ भा.दं.वि. (भारतीय दंड संहिता) की धारा 341, 323, 325, 307, 447, 504, 506, 34 के अंतर्गत आरोप पत्र

प्रस्तुत किया गया और फरार पाए गए आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित रखी गई। इसके बाद, 08.07.2015 को विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत संज्ञान लिया। 24.07.2015 को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। विद्वान निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध (भारतीय दंड संहिता) भा.दं.वि. की धारा 307/34 और 325/34 के अंतर्गत आरोप तय किए। अपीलकर्ताओं को आरोप पढ़कर सुनाए गए और समझाए गए, जिस पर उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाए जाने की मांग की।

5. अभियुक्तों को दोषी साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाहों से पूछताछ की। अ.सा.-1 पोलो मंडल, अ.सा.-2 जयकांत मंडल, अ.सा.-3 पूनम कुमारी, अ.सा.-4 राजीव कुमार (मामले के सूचक), अ.सा.-5 डॉ. धीरेंद्र कुमार, और अ.सा.-6 मनोज कुमार सिंह (मामले के जांच अधिकारी)।

अभियोजन पक्ष ने अभिलेख पर उपलब्ध निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्यों पर भरोसा किया है:-

प्रदर्श. 1-लिखित आवेदन पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर।

प्रदर्श. 2-घायल अहिल्या देवी की चोट की रिपोर्ट।

प्रदर्श. 3-चार्ज शीट।

प्रदर्श. 3/1-आरोप पत्र पर ओ/सी पीरीबाजार के हस्ताक्षर।

प्रदर्श. 4-औपचारिक प्राथमिकी पर पीरी बाजार पुलिस अधीक्षक आशुतोष कुमार के हस्ताक्षर।

6. अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रति-परीक्षण और दं.प्र.सं की धारा 313 के तहत दिए गए बयान से अपीलकर्ताओं का बचाव पूरी तरह से इनकार का है। हालाँकि, उन्होंने अपना बचाव नहीं किया।

7. पक्षकारों को सुनने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय अपीलार्थियों को दोषी ठहराने और उन्हें सजा देने के लिए प्रसन्न था जैसा कि निर्णय के शुरुआती कंडिका में संकेत दिया गया है।

8. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रबी भूषण को पर्याप्त समय तक सुना गया। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी गई हैं:-

अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि प्राथमिकी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हमले का कोई विशेष आरोप नहीं है और प्राथमिकी उक्त बिंदु पर पूरी तरह से मौन है। उन्होंने आगे दलील दी है कि प्राथमिकी के अवलोकन से आगे पता चलता है, घटनास्थल सूचक का द्वार है और अपीलकर्ताओं और अन्य द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार लाठी, डंडा और खंती है और हमलावर चार हैं और अभियोजन पक्ष की प्रारंभिक कहानी के अनुसार सूचक ने स्वयं कहा है कि घायल होने के बाद सूचक की माँ गिर पड़ी और शोर सुनकर वह घटनास्थल पर दौड़ता हुआ आया। सूचक के इस कथन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सूचक कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी है कि सूचना देने वाले ने स्वयं कहा है कि उसकी माँ के सिर पर चोट लगी है। लेकिन उसे अदालत में पेश नहीं किया गया है और जाँच अधिकारी ने यह कहते हुए उसका साक्ष्य दर्ज नहीं किया है कि वह साक्ष्य देने के लिए सचेत स्थिति में नहीं थी। उन्होंने आगे दलील दी है कि जाँच अधिकारी के बयान से भी यह स्पष्ट है कि वह अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने में विफल रहे क्योंकि उन्होंने प्रति-परिक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से कहा है कि वह कई बार घटनास्थल पर गए थे, लेकिन केस डायरी में यह दर्ज नहीं किया गया और उन्होंने फिर कहा कि पीड़िता अपनी बेटी के घर गई थी इसलिए वह पीड़िता से नहीं मिल सके। उन्होंने आगे दलील दी है कि जाँच अधिकारी की जाँच उनके वैधानिक कर्तव्य के संबंध में अपूर्ण है, जो कानून का आदेश है। उन्होंने आगे दलील दी है कि जाँच

अधिकारी ने घटनास्थल के निवासियों के बयान दर्ज नहीं किए हैं और वह इस बारे में स्पष्ट बयान देने में असमर्थ हैं कि नवल पांडे, पोलू मंडल और जयकांत मंडल घटनास्थल के निवासी हैं या नहीं। घटनास्थल के बिंदु पर, जाँच अधिकारी का बयान और (अ.सा.-4) का बयान बिल्कुल असंगत है। सूचक (अ.सा.-4) ने प्रति-परिक्षण के दौरान बताया है कि घटनास्थल के उत्तर दिशा में हमारी आंशिक भूमि है और पश्चिम दिशा में खाली भूमि है। जाँच अधिकारी (अ.सा.-6) ने कहा है कि घटनास्थल के उत्तर में गोली मंडल का घर है और पश्चिम में सूचक का घर है। घटनास्थल के दोनों ओर जाँच अधिकारी (अ.सा.-6) और सूचक (अ.सा.-4) के बयान घटनास्थल (पी.ओ.) की सीमा के बिंदु पर एक-दूसरे से बिल्कुल असंगत और विरोधाभासी हैं। उन्होंने आगे कहा है कि अभियोजन पक्ष वर्तमान मामले में घटनास्थल को साबित करने में विशेष रूप से विफल रहा है, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो जाता है। हथियार के बिंदु पर, अ.सा.-1 का बयान अभियोजन पक्ष की कहानी के प्रारंभिक संस्करण से बिल्कुल मेल नहीं खाता क्योंकि अ.सा.-1 ने कहा कि सभी ने सूचक की माँ पर पैना से हमला किया है जबकि अभियोजन पक्ष की प्रारंभिक कहानी में कहा गया है कि सभी ने सूचक की माँ पर लाठी, डंडा और खंती से हमला किया है। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि यदि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी सत्य भी पाई जाती है, तब भी, उपलब्ध तथ्यों और मामले के साक्ष्यों के आधार पर, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 307 सहपठित धारा 34 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि इसके अलावा, अभियोजन पक्ष की कहानी भी संदिग्ध है क्योंकि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे कथित घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं जैसा कि अभियोजन पक्ष की कहानी के प्रारंभिक संस्करण से पता चलता है। न तो सूचक पीड़ित है और न ही पीड़ित को न्यायालय में पेश किया गया है और न ही किसी अभियोजन पक्ष के गवाह ने घटनास्थल पर मौजूद अन्य अभियोजन पक्ष के गवाह का नाम उजागर किया है।

9. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री मुकेश्वर दयाल ने दलील दी कि प्राथमिकी के अवलोकन से ही यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता और अन्य व्यक्ति सूचक के दरवाजे पर आए और गाली-गलौज करने लगे और उन्होंने सूचक की माँ पर मामला वापस लेने का दबाव बनाया और जब सूचक की माँ ने गाली-गलौज करने से मना किया, तो उन्होंने सूचक की माँ पर लाठी, डंडा और खंती से हमला किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अ.सा.-4, जो सूचक और मामले का प्रत्यक्षदर्शी है, ने कहा है कि सभी ने खंती से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता के सिर पर चोट आई। उन्होंने आगे दलील दी कि अ.सा.-1 ने यह भी कहा है कि अपीलकर्ताओं और अन्य ने पीड़िता के सिर पर पैना से हमला किया। अ.सा.-3 ने यह भी कहा है कि अपीलकर्ताओं और अन्य ने पीड़िता के सिर पर खंती से हमला किया। अ.सा.-5 डॉ. धीरेंद्र कुमार, जिन्होंने पीड़िता का परीक्षण किया, ने भी अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया है क्योंकि उन्हें पीड़िता के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने आगे तर्क दिया है कि जाँच अधिकारी ने घटनास्थल की पहचान कर ली है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया है। उन्होंने आगे दलील दी है कि इस घटना के पीछे एक मकसद था, जो साबित हो चुका है कि अपीलकर्ता और अन्य लोग सूचक की माँ पर मामला वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे थे और यह मामला विवाद का मूल बिंदु बन गया है। उन्होंने आगे दलील दी कि सभी अपीलकर्ताओं ने इस तरह से काम किया है कि घटना को अंजाम देने का उनका इरादा एक जैसा था। इस प्रकार, दोषसिद्धि का फैसला और सजा का आदेश कानून के ठोस सिद्धांत पर आधारित है और इसलिए, आलोचना किए गए फैसले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. मैंने आक्षेपित निर्णय, विचारण न्यायालय के आदेश और अभिलेखों का अवलोकन किया। मैंने पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंदी तर्क पर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, गहन विचार किया है।

11. भां.द.वि. की धारा 307 और धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के आलोक में, विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किए गए गवाहों के साक्ष्यों का मूल्यांकन, विश्लेषण और जांच करना आवश्यक है।

12. अ.सा.-1 पोलो मंडल, हालांकि कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा कर रहा है, लेकिन वह संयोग से प्रत्यक्षदर्शी है क्योंकि जब वह राजमिस्त्री को बुलाने गया, तो उसने पाया कि पीड़िता अहिल्या देवी पर अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों ने मिलकर हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता के सिर पर चोट आई। अ.सा.-1 ने गवाही दी है कि अपीलकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार केवल पैना था, जो अभियोजन पक्ष की कहानी से पूरी तरह मेल नहीं खाता। उसने यह भी गवाही दी कि घटना पीड़िता के घर के आंगन में हुई थी, और प्राथमिकी से पता चलता है कि घटना सूचना देने वाले के घर के गेट पर हुई थी, जो कि एक-दूसरे से बिल्कुल विरोधाभासी और असंगत है।

13. अ.सा.-2 जयकांत मंडल कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, बल्कि वह सुनी-सुनाई बातों पर आधारित गवाह है।

14. अ.सा.-3 पूनम कुमारी, सूचक (अ.सा.-4) की पत्नी हैं। इस गवाह ने कहा है कि अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों ने पीड़िता पर हमला करने के लिए खंती का इस्तेमाल किया, जो अ.सा.-1 पोलो मंडल के बयान से बिल्कुल मेल नहीं खाता। इस गवाह ने कहा है कि घटना घर के अंदर यानी आंगन में हुई थी। घटनास्थल के बिंदु पर, उसका बयान अभियोजन पक्ष की कहानी के प्रारंभिक संस्करण से बिल्कुल विरोधाभासी है। उसका बयान उसके अपने बयान से बिल्कुल विरोधाभासी है जिसमें उसने कहा है कि शोर सुनकर वह घर के बाहर आई और घटना घर के अंदर हुई। उसने कहा है कि वह यह नहीं बता सकती कि किसने लाठी से और कितनी बार मारा और वह यह भी नहीं बता सकती कि किसने खंती से और कितनी बार मारा।

15. अ.सा.-4 राजीव कुमार इस मामले के सूचक हैं। इस गवाह ने अपनी प्राथमिकी के प्रारंभिक संस्करण में कहा है कि जब गाली-गलौज का विरोध किया गया, तो अपीलकर्ताओं और अन्य ने उसकी माँ पर लाठी, डंडा और खंती से हमला किया, लेकिन मुकदमे के दौरान उसने कहा कि उसकी माँ द्वारा मामला वापस लेने से इनकार करने पर, अपीलकर्ताओं और अन्य ने खंती से उसकी माँ पर हमला किया और उसने अभियोजन पक्ष की कहानी को विशेष रूप से इस तरह पेश किया कि घटना उसकी उपस्थिति में हुई, जो अभियोजन पक्ष की कहानी के प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं थी।

इस तरह, कथित घटना की उत्पत्ति, घटना के तरीके और घटना के स्थान के बारे में उनका संस्करण पूरी तरह से विरोधाभासी है। इस तरह, उनके साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं और उनके साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

16. अ.सा.-5 डॉ. धीरेंद्र कुमार, जिन्होंने पीड़िता की जाँच की और उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:-

- (i) सिर के बाईं ओर 5" x 1/4" x हड्डी तक गहरा घाव।
- (ii) छाती के बाईं ओर दर्द की शिकायत।
- (iii) कमर के बाईं ओर 2" x 1" का घर्षण और दर्द।
- (iv) पीठ के दाहिने कंधे के क्षेत्र में 2 1/2" x 3/4" का घर्षण।
- (v) शरीर में दर्द और बाईं आँख में दर्द की शिकायत।

चोट का कारण- कुंद और कठोर पदार्थों से।

चोट का समय- 06 घंटे के भीतर।

एम.आई.- दाहिनी क्लेराइड के पास छाती पर तिल।

चोट की रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं और किसी कठोर और कुंद पदार्थ से लगी हैं चोट संख्या 1 को छोड़कर, जो सिर के बाईं ओर 5" x 1/4" x हड्डी तक गहरा एक कटा हुआ घाव है। अन्य चोटें या तो घर्षण से हैं या दर्द

या बदन दर्द की शिकायत करती हैं। चोट की रिपोर्ट भी घटना के तरीके की पुष्टि नहीं करती है, जैसा कि अभियोजन पक्ष की कहानी के प्रारंभिक संस्करण से स्पष्ट है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क बल देता है कि अपराध की प्रकृति तय करने वाले निर्णायक तथ्य अपराध करने का इरादा या ज्ञान हैं और इस मामले में, तथ्य और परिस्थितियाँ स्वयं स्पष्ट करती हैं कि अपीलकर्ताओं का ऐसा कोई इरादा या आवश्यक ज्ञान नहीं था जैसा कि अभियोजन पक्ष की कहानी के प्रारंभिक संस्करण में आरोपित किया गया है और यदि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में सही पाई जाती है, तब भी, डॉक्टर (अ.सा.-5) द्वारा बताई गई चोट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ भा.दं.वि. की धारा 307 और धारा 34 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

17. वर्तमान अपील में, प्राथमिकी के प्रारंभिक संस्करण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सूचक भी कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है क्योंकि वह शोर सुनकर घटनास्थल पर पहुँचा था और वह वर्तमान मामले का पीड़ित नहीं है। पीड़िता, जो सूचक की माँ है, को चोटें आईं लेकिन उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अदालत में पेश नहीं किया गया।

18. एआईआर 1954 एससी 51 में प्रकाशित हबीब मोहम्मद बनाम हैदराबाद राज्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जिस गवाह का साक्ष्य "कथा को उजागर करने" के लिए आवश्यक है, उसकी जाँच की जानी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय के कंडिका 14 में यह माना कि यह सत्य है कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिस गवाह का साक्ष्य "कथा को उजागर करने" के लिए आवश्यक है, उसे बुलाया जाना चाहिए। आपराधिक मुकदमों में इस एकमात्र सिद्धांत पर इस न्यायालय ने हबीब मोहम्मद बनाम हैदराबाद राज्य के मामले में सत्य को उजागर करने के लिए जोर दिया है।

19. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष की कहानी के प्रारंभिक संस्करण के अवलोकन से, न तो सूचक पीड़िता है और न ही कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी, जैसा कि पूर्वगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है और पीड़िता ही मुख्य गवाह है, जिसकी घटनास्थल पर उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता और जिसका साक्ष्य कहानी को सामने लाने के लिए आवश्यक है, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा उसे अदालत के समक्ष उस कारण से पेश नहीं किया गया है जो अभियोजन पक्ष को ही सबसे अच्छी तरह ज्ञात है। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं को उससे प्रति-परिक्षण करने के अवसर से वंचित किया गया है, जो अभियोजन पक्ष के लिए घातक है।

20. इसके अलावा, अ.सा.-1, जो कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा कर रहा है, लेकिन उसके साक्ष्य में कई खामियाँ, विरोधाभास और विसंगतियाँ हैं। प्राथमिकी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह घटनास्थल पर नहीं पाया गया, सिवाय मुखबिर (अ.सा.-4) के, जो शोरगुल सुनकर आया था। घटना के तरीके के बिंदु पर, इस गवाह ने कहा कि अपराध का हथियार पैना है लेकिन अभियोजन पक्ष की कहानी के प्रारंभिक संस्करण में अपराध का हथियार लाठी, डंडा और खंती है। अ.सा.-1 द्वारा इंगित घटना का स्थान अहिल्या देवी (पीड़िता) का आँगन है, लेकिन अभियोजन पक्ष की कहानी के प्रारंभिक संस्करण में, गेट घटना का स्थान है जो घटना के स्थान के बिंदु पर पूरी तरह से असंगत है और अ.सा.-1 द्वारा इंगित घटना स्थल की सीमा जांच अधिकारी और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा इंगित सीमा से पूरी तरह से असंगत है। इस प्रकार, अ.सा.-1 का विवरण घटनास्थल, घटना के तरीके और घटनास्थल की सीमा के बिंदुओं पर बिल्कुल असंगत है और उसका यह कथन भी बिल्कुल असंगत है कि वह घटनास्थल पर एक मिनट या दस सेकंड तक रहा था। अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के दौरान दिए गए सभी कथनों को ध्यान में रखते हुए, घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति अत्यंत संदिग्ध है और

उसका साक्ष्य विश्वास पैदा नहीं करता है और कथित घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता ।

21. अ.सा.-2 कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। वह सुनी-सुनाई बातों पर आधारित गवाह है। अभियोजन पक्ष की कहानी के संबंध में उसके साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

22. अ.सा.-3 ने कहा है कि अपीलकर्ताओं और अन्य ने खंती के ज़रिए मिलकर हमला किया, जो अभियोजन पक्ष की कहानी से पूरी तरह मेल नहीं खाता। उसने कहा है कि हल्ला सुनकर, वह घर के बाहर गई और उसने आगे कहा कि घटना घर के अंदर यानी आँगन में हुई, जो अभियोजन पक्ष की कहानी के शुरुआती संस्करण से पूरी तरह मेल नहीं खाता। वह यह नहीं बता सकती कि लाठी किसने और कितनी बार मारी। वह यह नहीं बता सकती कि खंती किसने और कितनी बार मारी। उसका बयान स्वतः विरोधाभासी है क्योंकि घटना घर के अंदर हुई थी और वह शोर सुनकर बाहर आई थी। उसका बयान घटना के तरीके और स्थान के मुद्दे पर काफी विरोधाभासी है और घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी बेहद संदिग्ध है। उक्त गवाह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य घटना के स्थान और तरीके के संबंध में कमियों और विरोधाभासों से भरे हैं और इसलिए, उसके बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

23. अ.सा.-5 डॉ. धीरेंद्र कुमार ने घायल व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटें पाईं:

- (i) सिर के बाईं ओर 5" x 1/4" x हड्डी तक गहरा घाव
- (ii) छाती के बाईं ओर दर्द की शिकायत।
- (iii) कमर के बाईं ओर 2" x 1" का घर्षण और दर्द।
- (iv) पीठ के दाहिने कंधे के क्षेत्र में 2 1/2" x 3/4" का घर्षण।
- (v) शरीर में दर्द और बाईं आँख में दर्द की शिकायत।

चोट का कारण- कुंद और कठोर पदार्थों से।

चोट का समय- 06 घंटे के भीतर।

एम.आई.- दाहिनी क्लेराइड के पास छाती पर तिल

डॉक्टर की राय में चोट की रिपोर्ट के अनुसार, सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं और किसी कठोर और कुंद पदार्थ के कारण लगी हैं। चोट संख्या 1 को छोड़कर, अन्य चोटों में या तो दर्द या घर्षण की शिकायत है और अभियोजन पक्ष की कहानी, जैसा कि सूचक ने स्वयं बताया है, यह है कि अपीलकर्ताओं सहित चार व्यक्तियों ने लाठी, डंडे और खंती से एक साथ हमला किया। यहाँ तक कि चोट की रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि नहीं करती है और डॉक्टर ने भी स्वीकार किया है कि ऐसी चोटें किसी कठोर पदार्थ पर गिरने से भी हो सकती हैं। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि पीड़ित को गिरने के कारण चोट लगी।

24. अ.सा.-6 जाँच अधिकारी है। उसका बयान कमज़ोरियों से भरा है क्योंकि वह वैधानिक कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा क्योंकि उसने खुद कहा है कि वह कई बार घटनास्थल पर गया था, लेकिन केस डायरी में उसका विवरण दर्ज नहीं किया गया। एक जगह उसने कहा है कि पीड़िता बोलने में असमर्थ थी, इसलिए उसने उसका बयान दर्ज नहीं किया और दूसरी जगह उसने कहा है कि पीड़िता अपनी बेटी के घर गई थी, इसलिए वह उससे नहीं मिल सका। इस गवाह ने घटनास्थल के निवासियों का बयान भी दर्ज नहीं किया है। उसने घटनास्थल की सीमा के बारे में जो बयान दिया है, वह अ.सा.-4 (सूचना देने वाले) द्वारा बताई गई सीमा से बिल्कुल मेल नहीं खाता। इस प्रकार, उसका वैधानिक कर्तव्य कमज़ोरियों से भरा है और उसके कथन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

25. इस अपील में विचारणीय मुख्य मुद्दा यह है कि क्या भा.दं.वि की धारा 307 और धारा 34 के अंतर्गत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि कायम रह सकती है?

26. भा.दं.वि. की धारा 307 के तहत अपराध गठित करने के लिए, अपराध के निम्नलिखित तत्व मौजूद होने चाहिए;

(क. हत्या करने से संबंधित इरादा या ज्ञान) और

(ख. इसके लिए कोई कार्य करना।

भा.दं.वि. की धारा 307 के प्रयोजन के लिए, मुख्य बात इरादा या ज्ञान है, न कि इरादे को पूरा करने के उद्देश्य से किए गए वास्तविक कार्य का परिणाम। यह धारा स्पष्ट रूप से ऐसे कार्य की कल्पना करती है जो मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किया जाता है, लेकिन हस्तक्षेप करने वाली परिस्थितियों के कारण जो इच्छित परिणाम लाने में विफल रहता है। कारण का इरादा या ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हत्या का गठन करने के लिए आवश्यक हो। इरादे या ज्ञान के अभाव में, जो धारा 307 भा.दं.वि. का एक आवश्यक घटक है, हत्या के प्रयास का कोई अपराध नहीं हो सकता।

27. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों का उल्लेख करना उचित है:

तकदीर समसुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य और एआईआर 2012 एससी 37 में दर्ज एक अन्य मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 10(ii) में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"10 (ii). इस न्यायालय ने लगातार यह माना है कि एक सामान्य नियम के रूप में, न्यायालय एक गवाह की गवाही पर कार्य कर सकता है और कर सकता है, बशर्ते वह पूरी तरह से विश्वसनीय हो। किसी व्यक्ति को केवल एक गवाह की गवाही के आधार पर दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। यही साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 का तर्क है। लेकिन अगर गवाही पर संदेह है, तो न्यायालय पुष्टि पर जोर देगा। वास्तव में, संख्या या मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। समय-सम्मानित सिद्धांत यह है कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए, गिना नहीं जाना चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या साक्ष्य में सत्यता है, वह ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है या अन्यथा। कानूनी प्रणाली ने गवाहों की संख्या, बहुलता या बहुलता के बजाय साक्ष्य के मूल्य, भार और गुणवत्ता पर जोर दिया है।

इसलिए, एक सक्षम न्यायालय के लिए यह स्वतंत्रता है कि वह पूरी तरह से एक अकेले गवाह पर भरोसा करे और दोषसिद्धि दर्ज करे। इसके विपरीत, यदि वह साक्ष्य की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है, तो वह कई गवाहों की गवाही के बावजूद भी आरोपी को बरी कर सकता है।

ब्रह्म स्वरूप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 2011 एससी 280 में रिपोर्ट किए गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के कंडिका 22 में निम्नलिखित निर्णय दिया:

"22. जहाँ घटना का कोई गवाह खुद घटना में घायल हुआ हो, ऐसे गवाह की गवाही आम तौर पर बहुत विश्वसनीय मानी जाती है, क्योंकि वह एक ऐसा गवाह होता है जिसके साथ अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी होती है और वह किसी को झूठा फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावर(ओं) को नहीं छोड़ेगा। "घायल गवाह को बदनाम करने के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता होती है।

रणजीत सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 2011 एससी 255 में प्रकाशित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 17 में निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"17. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, एक गवाह द्वारा दिया गया विश्वसनीय साक्ष्य किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होगा, जबकि आधा दर्जन गवाहों द्वारा दिया गया विश्वसनीय न होने वाला साक्ष्य दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

मनो दत्त एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 4 एससीसी 79 में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के कंडिका 30 में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"30.....आम तौर पर, एक घायल गवाह को अधिक विश्वसनीयता प्राप्त होगी क्योंकि वह स्वयं पीड़ित है और इस प्रकार, ऐसे व्यक्ति के लिए घटना का गलत संस्करण

बताने, या किसी को भी झूठे तरीके से शामिल करने और बदले में असली दोषी को बचाने का कोई अवसर नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशन चंद व अन्य (2004) 7 एससीसी 629 में दर्ज मामले में भी इसी तरह का मत दोहराया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुहर लगे गवाह की गवाही की अपनी प्रासंगिकता और प्रभावकारिता होती है। यह तथ्य कि गवाह को घटना के समय और स्थान पर चोटें आईं, उसकी इस गवाही को पुष्ट करता है कि वह घटना के दौरान मौजूद था।

28. वर्तमान मामले में, तथ्यात्मक गवाह और उनके कथन में कमियाँ और विरोधाभास हैं, हालाँकि वे कथित घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष की प्रारंभिक कहानी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सूचक शोरगुल सुनने के बाद उपस्थित होता है। इस प्रकार, सूचक (अ.सा.-4) कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अभियोजन पक्ष की प्रारंभिक कहानी से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह घटनास्थल पर नहीं पाया गया सिवाय सूचना देने वाले (अ.सा.-4) के, जिसकी उपस्थिति भी घटनास्थल पर संदिग्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रासंगिक निर्णय (2010) 13 एससीसी 657 (सुनील कुमार शंभूदयाल गुप्ता एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य) को उद्धृत करना आवश्यक है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियाँ, यदि मामूली प्रकृति की नहीं पाई जातीं, तो उस साक्ष्य पर अविश्वास करने और उसे बदनाम करने का आधार बन सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में, यदि साक्ष्य अन्य साक्ष्यों और पहले से दर्ज किए गए बयानों के साथ विरोधाभासी और असंगत पाया जाता है, तो गवाह विश्वास पैदा नहीं कर सकते। ऐसे मामले में, यह नहीं माना जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला उचित संदेह से परे साबित कर दिया है।"

29. इस संबंध में, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दं.प्र.सं. की आपराधिक अपील (खं.पी.) की धारा 120 संख्या 745/2015 में पारित दिनांक 03.03.2023 के निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:-

"आपराधिक कानून में, अभियोजन पक्ष का दायित्व प्रत्येक आरोप को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा सिद्ध करना है। आपराधिक मामलों में दायित्व की सीमा केवल संभावनाओं की प्रबलता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि, जिस मानक को पूरा करने की आवश्यकता है वह 'सभी उचित संदेहों से परे' है।"

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण गोपाल एवं अन्य के मामले में, जो 1988 एआईआर 2154 में रिपोर्ट किया गया था, यह देखा गया है कि:-

"किसी व्यक्ति को, निस्संदेह, यह गहरा अधिकार है कि उसे ऐसे अपराध के लिए दोषी न ठहराया जाए जो उचित संदेह से परे साक्ष्य के मानक द्वारा स्थापित न हो।"

30. उपरोक्त अनुच्छेदों में उल्लिखित निर्णयों के संबंध में की गई चर्चा के आलोक में, वर्तमान मामले और साक्ष्य को आसानी से स्थापित कानूनी प्रस्ताव की कसौटी पर परखा जा सकता है।

31. वर्तमान मामले में, विवेकपूर्ण और व्यावहारिक रूप से सूचक, जिसने कहानी के प्रारंभिक संस्करण को गति दी, ने बताया है कि अपीलकर्ताओं और अन्य ने मिलकर सूचक की माँ पर हमला किया और इस घटना के पीछे का कारण मामले को वापस लेना है और घटना का मूल बिंदु यह है कि जब अपीलकर्ताओं और अन्य के साथ दुर्यवहार का विरोध किया गया, तो सूचक की माँ पर हमला हुआ और अभियोजन पक्ष की कहानी के प्रारंभिक संस्करण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हल्ला होने पर, सूचक अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इस प्रकार, अ.सा.-4 (सूचक) घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों जैसे अ.सा.-1 और अ.सा.-3 की उपस्थिति बहुत ही संदिग्ध थी क्योंकि

यह प्राथमिकी और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से भी स्पष्ट है, हालाँकि, वे तथ्यात्मक गवाह हैं और व्यक्तिगत रूप से, वे घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष की कहानी के प्रारंभिक संस्करण में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि घटना का मूल बिंदु तब हुआ जब दुर्व्यवहार का विरोध किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सूचक की माँ पर हमला हुआ। उक्त तथ्य का यह विशिष्ट दावा सूचना देने वाले (अ.सा.-4) के बयान में नहीं किया गया है, जिससे घटना के मूल बिंदु के संबंध में भी अभियोजन पक्ष की कहानी पर असर पड़ता है। अभियोजन पक्ष की कहानी के प्रारंभिक संस्करण से पता चलता है कि अ.सा.-4 ने यह नहीं कहा है कि अ.सा.-1 या अ.सा.-3 घटनास्थल पर मौजूद थे।

अभियोजन पक्ष की कहानी के प्रारंभिक संस्करण से ही, अ.सा.-1, अ.सा.-3 और अ.सा.-4 की उपस्थिति बहुत संदेहास्पद थी और अ.सा.-1 के बयान से यह स्पष्ट है कि उसने फुसफुसाकर भी नहीं कहा कि अ.सा.-3 या अ.सा.-4 घटनास्थल पर मौजूद थे। अ.सा.-3 के बयान से यह स्पष्ट है कि यह कभी नहीं बताया गया कि अ.सा.-1 और अ.सा.-4 घटनास्थल पर मौजूद थे और अ.सा.-4 के बयान से यह स्पष्ट है कि यह कभी नहीं बताया गया कि अ.सा.-1 या अ.सा.-3 घटनास्थल पर मौजूद थे। वर्तमान मामले में, मुख्य गवाह सूचनाकर्ता की माँ है, जिसकी घटनास्थल पर उपस्थिति संदेहास्पद नहीं है और उसकी जाँच भी नहीं की गई है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह की घटनास्थल पर उपस्थिति अत्यंत संदिग्ध है और कानून का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त के पक्ष में जाता है। ऐसी स्थिति में, अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जबकि पीड़िता/सूचक की माँ को चोट लगी थी और डॉक्टर पहले ही यह बता चुके हैं कि उक्त चोट किसी भी कठोर पदार्थ पर गिरने से लग सकती हैं और बचाव पक्ष द्वारा यह भी सुझाव दिया गया था कि उसे गिरने के कारण चोट लगी थी, हालाँकि, अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा इस सुझाव का खंडन किया गया है। ऐसी स्थिति में, मामले

के उक्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर, अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। इसके अलावा, तथ्यात्मक गवाहों यानी अ.सा.-1, अ.सा.-3 और अ.सा.-4 के बयान, हालांकि, वे प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा कर रहे हैं, उनके साक्ष्य घटनास्थल, घटनास्थल की विधि और सीमा के बिंदुओं पर कमियों और विरोधाभासों से भरे हैं।

32. उपरोक्त अनुच्छेदों में की गई सभी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का मूल्यांकन नहीं किया है कि क्या वर्तमान मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 307 (सहित 34) के तहत वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपराध बनता है, जिसमें पीड़ित की जांच नहीं की गई है और अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने घटनास्थल पर अन्य गवाहों की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा, तथ्यात्मक गवाहों जैसे कि अ.सा.-1, अ.सा.-3 और अ.सा.-4 के बयानों में घटना के तरीके, घटनास्थल और घटनास्थल की सीमा के संबंध में कई विसंगतियां, कमियाँ और विरोधाभास हैं और यह स्थापित कानून है कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना होगा और यह स्थापित सिद्धांत रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से गायब है और अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क बल पाता है क्योंकि इन सभी पहलुओं से, मुझे लगता है कि अ.सा.-1, अ.सा.-3 और अ.सा.-4 जैसे तथ्यात्मक गवाहों पर कथित घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है।

33. मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और संदेह का लाभ अपीलकर्ताओं के पक्ष में जाता है।

34. परिणामस्वरूप, मेरे विचार से, अभियोजन पक्ष का मामला जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कई कमियों से ग्रस्त है, और यह एक उपयुक्त मामला नहीं था जिसमें

दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती थी। विद्वान अधिनस्थ न्यायलय ने कानूनी त्रुटि के साथ-साथ स्थापित आपराधिक न्यायशास्त्र के मद्देनजर मामले के तथ्यों की भी अवहेलना की। अतः, दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश को दरकिनार किया जाता है और यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता हिरासत में हैं। यदि किसी अन्य मामले में उनकी सजा की गारंटी नहीं है, तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

35. यदि कोई अंतरिम आवेदन है, तो उसका भी निपटारा कर दिया गया है।

36. इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल के अधीक्षक को अनुपालन और अभिलेख के लिए प्रेषित की जाए।

37. इस मामले के अभिलेख भी संबंधित विचारण न्यायलय को तुरंत लौटा दिए जाएं।

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

शहजाद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।